

यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खनन अधिकारी चमोली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला खनन अधिकारी चमोली के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार मौर्य ले0प0 व श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.17 से 23.05.17 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मक:** प्रथम लेखापरीक्षा है।

वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रु लाख में)
2012-13	465.07
2013-14	118.86
2014-15	119.08
2015-16	163.36
2016-17	175.52

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन: बजट प्राप्त नहीं होता है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव (खनन) – अपर सचिव/निदेशक – अपर निदेशक

|

संयुक्त निदेशक खनन – संयुक्त निदेशक भूविज्ञान – रसायनक

|

|

|

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधि°- खान अधि°

उपनिदेशक भूविज्ञान- सहायक भूविज्ञान

सहा° रसायनज्ञ- प्रा° सहा°रसायनज्ञ

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में जिला खनन अधिकारी गोपेश्वर चमोली को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खनन अधिकारी गोपेश्वर, की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: माह 03/17, 10/15 और 3/14 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षाभाग-II 'अ'

प्रस्तर 01-स्टाम्प शुल्क का न्यूनारोपण ₹8.66 लाख

इण्डियन स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 के अनुसार वध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लये अधकृत, पुलस अधकारी के सवाय, सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके समक्ष उसके कर्तव्य के सम्पादन मे कोई ऐसा वलेख प्रस्तुत कया जाये या आ जाये, जो उसकी राय मे स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य है और उसे प्रतीत हो क वह वलेख यथा व ध स्टाम्पित नही है, से जब्त् करेगा।

पुन धारा 35 के अनुसार वध या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य लेने के लये अधकृत कसी व्यक्ति द्वारा ऐसे वलेख को जो शुल्क से प्रभार्य है, साक्ष्य स्वीकार नही कया जायेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा या कसी सार्वजनिक अधकारी द्वारा उसको कार्यान्वित रजिस्ट्रीकृत या प्रमाणत नही कया जायेगा, जब तक वह वलेख यथा व ध स्टाम्पित न हो। रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17(1)(घ) मे यह प्रावधान कया गया है क वर्षा नवर्ष या क वर्ष से अधक कसी अवध के लए या वार्षक कराया सुरक्षत करने वाली अचल सम्पत्त की लीज के लेखपाल का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। लीज के जो वलेख क वर्ष से कम अवध के लये है उनका रजिस्ट्रीकरण ऐच्छिक है कन्तु उसके प्रतिफल की धनराश पर स्टाम्प शुल्क अदा कया जाना अपेक्षत है।

पुन: महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड के पत्रांक 827/म0नि0नि0/2013-14 दिनांक 23.12.13 जो समस्त जिला धकारी को संबोधत है के द्वारा यह निर्देश दिये गये है क समस्त कार्यालयध्यक्ष भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के आलोक मे उनके कार्यालय मे वगत 8 वर्षो मे निष्पादित कये गये व भन्न प्रकार के वलेखो का परीक्षण कर ले एवं यदि कसी प्रकरण मे स्टाम्प कमी का मामला दृष्टिगोचर हो तो संबधत अभलेखों की प्रति अपनी आख्या सहित यथाशीघ्र अपने जनपद के कलेक्टर कार्यालय मे उपलब्ध कराते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराये।

कार्यालय जिला खनन अधकारी, गोपेश्वर (चमोली) की नमूना लेखा परीक्षा मे कार्यालय के स्टोन केशर /भण्डारण तथा पट्टा वलेखों की पत्रावलियों की जांच मे निम्न तथ्य संज्ञान मे आये-

1. तीन स्टोन क्रेशर के स्वा मयो को स्टोन क्रेशर स्थापना/भण्डारण हेतु व्यक्तियों द्वारा अपनी भूम कराये पर दी गई तथा अनुबन्ध/करायेनामे पर मात्र ₹50 या ₹100 का स्टाम्प स्टाम्पित किया गया जब क नियमानुसार अनुलग्नक -1 के कालम-9स के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय था एवं कालम-10 के अनुसार स्टाम्प शुल्क कम था। उक्त प्रकार से वर्णित मामले कलेक्टर स्टाम्प को सन्दर्भित नहीं कये जाने से ₹52912 के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई तथा इन वलेख पत्रों को उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत न कराये जाने के कारण निबंधन फीस के रूप में भी राजस्व क्षति हुई।
2. श्री धनसंह राणा पुत्र श्री लालसंह राणा, ग्राम व पोस्ट -लाता, पटवारी क्षेत्र-तपोवन तहसील- जोशीमठ, जिला -चमोली को तिथि 4/5 से 12/6 जिसकी अवधि 01 वर्ष 09 माह थी तथा पट्टे की वार्षिक धनराशि 7333333 थी, स्वीकृत हुआ था। नियमानुसार एक वर्ष से अधिक कन्तु पांच वर्ष से अधिक अवधि की लीज पर वार्षिक पट्टा धनराशि के औसत के तीन गुने पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय था। इसलए वार्षिक पट्टा धनराशि ₹7333333 की तीन गुना ₹21999999 पर दो प्रतिशत ₹4400000 का स्टाम्प शुल्क देय था, जब क वलेख पत्र पर मात्र ₹146700 के स्टाम्प स्टाम्पित थे।

उपरोक्त प्रकार से ₹293300 (440000-146700) के स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।

3. श्री हरीशसंह भण्डारी पुत्र स्व० मुरलीसंह भण्डारी, ग्राम-बड़ागांव, पटवारी क्षेत्र व तहसील जोशीमठ, जिला -चमोली को दिनांक 10.02.15 से 30.12.16 जिसकी अवधि 01 वर्ष 10 माह 20 दिन थी तथा पट्टे की वार्षिक धनराशि 1800000 थी, स्वीकृत हुआ था। नियमानुसार एक वर्ष से अधिक कन्तु पांच वर्ष से अधिक अवधि की लीज पर वार्षिक पट्टा धनराशि के औसत के तीन गुने पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय था। इसलए वार्षिक पट्टा धनराशि ₹18000000 की तीन गुना ₹54000000 पर दो प्रतिशत ₹1080000 का स्टाम्प शुल्क देय था, जब क वलेख पत्र पर मात्र ₹560000 का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया था।

उपरोक्त प्रकार से ₹520000 (1080000-560000) का स्टाम्प शुल्क की क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगत कये जाने पर बिन्दु (1) के संबंध में इकाई ने उत्तर दिया क उत्तरांचल शासन, औद्योगिक विकास वभाग की अधिसूचना सं० 617/सात.05/158-ख/2004 दिनांक 14.03.05 द्वारा प्रस्थापित उत्तरांचल खनिज

(अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 के बिन्दु सं 11(ग) के अनुसार कसी ऐसी भूमि जो उसकी नहीं है या उसके ठसकी वैध करायेदारी में नहीं है का उपभोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा, उल्लिखित है।

उक्त बिन्दु में स्टाम्प शुल्क कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

उक्त के अनुसार भण्डारण हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि ववादित नहीं होनी चाहिए, भूमि (वर्ग-क) होनी चाहिए, से संबंधित है बिन्दु सं 0- (2) व (3) के संबंध में अवगत कराया गया कि कसी भी स्वीकृत होने वाले खनन पट्टे से संबंधित मूल्यांकन आख्या अर्थात् वार्षिक पट्टा धनराशि अपरिहार्य भारकमा सक कश्त प्रतिभूति की धनराशि हेतु आख्या जिला अधिकारी महोदय की प्रेषित की जाती है साथ ही प्रति लप अन्य के साथ-साथ जिला उप निबंधक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि खनन पट्टा वलेख निष्पादन हेतु आंगणत वार्षिक पट्टा धनराशि वर्तमान माह से दिनांक 30.09.16 तक की अवधि हेतु लगने वाले स्टाम्प शुल्क के संबंध में सूचित करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्टाम्प पेपर पर जिला कार्यालय से वलेख टंकित होने उपरान्त उसका पंजीकरण संबंधित उप निबंधन अधिकारी के कार्यालय में किया जाता है। स्टाम्प शुल्क कम या अधिक होने के संबंध में जिला उप निबंधन अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

इकाई द्वारा पट्टा वलेख के संबंध में उनके कार्यालय में होने वाली पूरी प्रणाली का तो वस्तुतः ववरण दिया गया लेकिन स्टाम्प से संबंधित जानकारी न होने के कारण तथा प्रकरण की गम्भीरता को न समझते हुए उप निबंधक अधिकारी से जानकारी प्राप्त की सलाह दी गयी।

अतः 8.66 लाख के स्टाम्प शुल्क न्यूनारोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तर 01:- वभागीय उदासीनता के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹147.30 लाख

जनपद चमोली के तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम जयकण्डी स्थित अलकनन्दा नदी तल पर उपलब्ध उपखनिज क्षेत्र (खसरा नं 955 मु0 क्षे0) (4.90 है0) में खनन/खुगान करने के लिये जिला अधिकारी चमोली द्वारा दिनांक 14.11.13 को निवदा का प्रकाशन किया गया था। उक्त के सापेक्ष खनन/पट्टा आवंटित होने की कार्यवाही पूर्ण न होने की स्थिति में जिला अधिकारी चमोली द्वारा पुनः दिनांक 23.01.14 को अल्पकालक निवदा सूचना का प्रकाशन करते हुये सर्वाधिक सावर्जनिक निवदा दाता भरने वाले श्री नन्दन सिंह पुत्र स्व0 श्री शंकर सिंह वष्ट ग्राम निवासी पलंग तहसील एवं जिला चमोली के पक्ष 17459000 प्रतिवर्ष के रायल्टी के आधार पर खनन पट्टा आदेश (एम0एम0 -10) जिला अधिकारी, दिनांक 22.02.14 को निम्न शर्तों के साथ निर्गत कर दिया गया था पट्टा धारक को वर्ष में (वर्षा ऋतु को छोड़कर) ₹139650/- टन का खनन करना है तथा ₹1939889/- की मासिक रायल्टी निर्धारित किया गया था। खनन/खुगान पट्टा तीन वर्ष या 30 सितम्बर 2016 तक वैध था।

शर्तें: 1. उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 1971/VII-1/130-29/ दिनांक 23 सितम्बर 2013 में वर्णित शर्तों का पालन करना है।

2. पट्टाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 तथा उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। उक्त निर्धारित शर्तों के आधीन खनन/खुगान कार्य करेगा तथा वार्षिक अपरिहार्य रायल्टी को 9 मासिक कश्तों के रूप अग्रम प्रत्येक माह की 20 तारीख तक राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

3. अग्रम में मासिक कश्त जमाने किये जाने की स्थिति में 15% वार्षिक ब्याज से जा करने का नोटिस दिया जायेगा पुनः न जमा करने की स्थिति में 18% की वार्षिक दर से जमा करने की नोटिस जारी की जायेगा पुनः न जमा करने की स्थिति में अग्रम एवं प्रतिभूति का समायोजन कर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।

4. मासिक अग्रम कश्त 20 तारीख तक जमाने करने की स्थिति में खनिज के खनन/खुगान के परिवहन हेतु एम0एम0-11 प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

जिला खनन अधिकारी चमोली के उक्त पट्टाधारक की पत्रावली की जांच में पाया गया कि पट्टा धारक द्वारा माह 02/2014 से माह 12/2014 तक का अग्रम कुल धनराश

₹15519112/- (1939889X8) जमा किया गया था परन्तु उक्त माहों के उपरान्त 01/2015 से 06/2015 तक की कुल ₹11639334 (1939889X6) की धनराश नहीं जमा की गयी थी जब क पट्टा धारक द्वारा उक्त माहों में खनन/घुगान 30349.90 टन का किया गया था एवं खनन/घुगान के परिवहन के लिये एम0एम0-11 माह 01/15, 02/15 एवं 04/15 में पट्टा धारक द्वारा प्राप्त किया गया था।

आगे अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया क पट्टाधारक द्वारा माह अक्टूबर 2015 से पुनः ₹698155 के मासिक कश्त के आधार पर अक्टूबर 2015 से जनवरी 2016 तक कुल ₹2792620 जमा किया गया था पुनः 02/16 से 06/16 तक की धनराश ₹3090775/- (698155X5=3090775) सम्प्रेक्षा तिथि तक नहीं जमा किया गया था जब क उक्त माहों प्राप्त किया गया था सफल पट्टाधारक श्री खनन/घुगान 22647.16 टन का किया गया था माह 02/2016 एवं 06/16 में पट्टा धारक भी नन्दन सिंह का मासिक कश्त 1939889 से माह 10/2015 में ₹698155 किये जाने का औचित्य पता नहीं चला जब क आधार कुल ₹ 17456250/- था आधार मूल्य के अनुसार भी मासिक कश्त ₹1939583.333 होता है।

इस प्रकार ₹17430109/- की धनराश पट्टा धारक द्वारा नहीं जमा किया गया था तथा उक्त पर जमा किये जाने की तिथि तक ब्याज भी देय है।

उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर वभाग द्वारा उत्तर में बताया गया क मासिक अग्रिम कश्त के समायोजन के संबंध मार्गदर्शन हेतु निदेशक को पत्र प्रेषित किया गया तथा उच्च स्तर से कोई आदेश प्राप्त न होने की दृष्टिगत रखते हुए खनन पत्र एम0एम0-11 जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त के संबंध में अधिसूचना/कार्यालय ज्ञाप की शर्त के अनुसार मासिक अग्रिम कश्त जमा न होने पर एम0एम0-11 निर्गत नहीं किया जाना था।

अतः ₹147.30 लाख के राजस्व क्षति तथा ब्याज के हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 02-रायल्टी जमा न कये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹32.30 लाख

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1917XII- I/130-ख/2013 दिनांक 23.09.13 के बिन्दु (a) में यह वर्णित है कि कच्ची कारणों से जिन-जिन क्षेत्रों का राज्य सरकार की अनुमति के उपरान्त जिला अधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा श्रोत क्षेत्र के संबंध में आपत्त दर्ज की जाती है जिसमें आवेदक की ओर से कोई गलती नहीं होने की दशा में निदेशक की अनुमति के उपरान्त अनुमति शासन द्वारा वापस ली जायेगी ऐसी परिस्थिति में स्वीकृत प्रतिभूति राश तथा अग्रम कश्त आवेदक को वापस कर दी जायेगी। यदि निकासी हुई तो तदनुसार निवदत मूल्य के अनुरूप आगणन कर धनराश जमा करायी जायेगी तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप के वज़्जितकरण, निवदा प्रपत्र एवं शर्तों के बिन्दु (9) भुगतान की प्रक्रिया के (पांच) में उल्लिखित है कि पट्टा निरस्तीकरण के उपरान्त जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर दूसरी निवदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अर्थात् अर्थात् जब तक दुबारा नयमत कार्य प्रारम्भ न हो जाय तब तक की अवधि हेतु उक्त क्षेत्रों को दैनिक निकासी के आधार पर स्थानीय लोगों को निकासी हेतु दिया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र में हो रहे प्रतिदिन के राजस्व हानि को पूर्व में आधारित सफल निवदाकार द्वारा जमा समाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र से वसूल किया जायेगा।

उक्त कार्यालय ज्ञाप के अनुसार जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के ग्राम अलगांव खसरा सं 127 क्षेत्र 3.001 हे० में उपलब्ध उपखनिज के खनन/चुगान के लिये निवदा के माध्यम से सार्वजनिक निवदा दाता श्री हरीश सिंह भण्डारी पुत्र श्री मुरली सिंह भण्डारी के पक्ष में जिला अधिकारी चमोली द्वारा 2000000 मासिक अग्रम (₹180000000 वार्षिक)

कश्त निर्धारित कर दिनांक 11.02.15 को खनन/चुगान का आदेश निर्गत कर दिया गया उक्त खनन/चुगान के द्वारा 53250 टन प्रति वर्ष चुगान किया जाना था तथा आधार मूल्य ₹6656250/- प्रति वर्ष (वर्षाऋतु छोड़कर) था।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा दिनांक 03.04.15 को पूर्व में हुई दैवीय आपदा के कारण नदी में अत्यधिक मात्रा में वोल्डर का भण्डारण रोज बजरी की उपलब्धता न होना तथा क्षेत्र में स्टोन क्रेशर प्लान्ट का होना तथा आर्थिक स्थिति दयनीय बता कर खनन लाट को निरस्त कये जाने का अनुरोध किया गया और उक्त का खनन/पट्टा आदेश दिनांक 24.07.15 को सरेण्डर करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। पुनः आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि लाटरी सस्टम के आधार पर दिनांक

12.02.16 को ₹750250 मा सक कश्त के आधार पर श्री प्रेम सिंह, के पटन स्वीकृत कर दिया गया ।

इस प्रकार दिनांक 24.07.15 से दिनांक 12.02.16 तक के मध्य दैनिक आधार पर राजस्व ₹32.30 लाख सफल नि वदा दाता श्री हरीश चन्द्र भण्डारी द्वारा नही जमा कये जाने से राजस्व क्षति हुई। ववरण निम्नानुसार है।

लाट का आधार मूल्य ₹6656250 वा र्षक

मा सक मूल्य ₹6656250/9=₹739583/-

माह 10/15, 11/15, 12/15, 1/16 का मूल्य =₹739583X4=₹2958332

11.02.2016 तक का मूल्य =₹739583/30X11=₹271180

कुल योग= ₹3229512

आवेदक की त्रुटि के संबंध में अवगत कराना है क दैवीय आपदा वर्ष 2013 में आयी थी, पर्यावरणीय आख्या वर्ष 2014 में होने पर 53250 घन मी0 चुगान की अनुमति दी गयी थी तथा क्षेत्र में वोल्डर है, की सूचना नि वदा में दी गयी थी तथा क्षेत्र का निरीक्षण करने के उपरान्त नि वदा भरे जाने का निर्देश था।

उक्त के संबंध में इंगत कये जाने पर वभाग अपने उत्तर में बताया गया क उक्त के संबंध में जिला कार्यालय से आख्या प्राप्त कया जाना उ चत होगा।

अतः जिला कार्यालय से उत्तर प्राप्त करने हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

इस प्रकार सफल नि वदा दाता द्वारा लाट सरेण्डर होने के उपरान्त तथा पुनः आवंटन के पूर्व की रायल्टी जमा न कराये जाने के कारण राजस्व क्षति ₹32.30 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 03-स्वीकृत मात्रा से अधिक भण्डारण पर अर्थदण्ड ₹2.00 लाख एवं रायल्टी ₹25.91 लाख का अनारोपण।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग अधिसूचना संख्या 1031/VII-1/2015/158-ख/ 2004 देहरादून, 31 जुलाई, 2015 के नियम 13 के उपनियम 2(ग) के अनुसार भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से आंगणत मात्रा से 2% से अधिक पायी जाती है या भण्डारण की मात्रा अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मात्रा का मलान करने पर 2% से अधिक भण्डारित मात्रा पर नियम-13(2)(ख) के अनुसार अर्थदण्ड धनराशि ₹200000/- के अतिरिक्त अवैध उत्खनिज खनिज परिवहन किये जा रहे खनिज/भण्डारित किये गये खनिज की मात्रा का वक्रय मूल्य (रायल्टी का पांच गुणा तक) की धनराशि उपरोक्तानुसार आंगणत कर वसूल की जायेगी।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग कार्यालय ज्ञाप संख्या 1033/VII-1/2015/146-ख/ 2010 देहरादून, 31 जुलाई, 2015 के उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर, ईट आदि) नीति 2015 के अनुसार पर्वतीय उपखनिज क्षेत्र (क्षेत्र-क) जिसमें जनपद-चमोली सम्मिलित है, में उपखनिज की रायल्टी दर तत्समय निर्धारित रायल्टी दर का 50% लागू होगा, साथ ही रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15% एवं विकास शुल्क रायल्टी का 10% अतिरिक्त रूप से देय होगा।

पुनः उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 अधिसूचना संख्या 211/VII-1/2015/24--ख/ 2007 देहरादून, 26 फरवरी, 2016 के उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 के बिन्दु -6 के अनुसार नदी तल से भन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स, बजरी/मट्टी, बैलास्ट संगल/महाडों के क्षरण से उत्पन्न मोरम/बालू के रायल्टी की दर 194.50 प्रति धनमीटर होगा।

कार्यालय जिला खनन अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) की नमूना लेखापरीक्षा में कार्यालय के स्टोन केशर एवं भण्डारण पत्रावलियों की जांच में निम्न तथ्य संज्ञान में आये-

1. पत्रांक 109/जि0टा0को0च0/अप0ख0भण्डारण/2016-17, दिनांक 9 जून, 2016 की जांच आख्या के अनुसार स्थापित किये जाने वाले स्टोन केशर संयंत्र के भूभाग को छोड़ते हुए लगभग 0.150 हेक्टेयर भूमि उपखनिज भण्डारण हेतु शेष थी जिस पर कुल लगभग 4500 घनमीटर उपखनिज का भण्डारण किया जा सकता था। इसको आधार

मानते हुए दिनांक 15 जून, 2016 को श्री धर्म सिंह भण्डारी पुत्र श्री इन्दु सिंह भण्डारी ग्राम व रा0उप0 निरीक्षक क्षेत्र-हेलंग तहसील जोशीमठ जनपद चमोली को 01 मार्च 2021 तक की अवधि हेतु 4500 घनमीटर उपखनिज (बालू, रेत, कंकरीट) के भण्डारण हेतु अनुमति दी गयी थी।

सितम्बर 2016 की मासिक ववरणी प्रपत्र -एल के अनुसार भण्डारणकर्ता के पास उपखनिज का प्रारम्भिक स्टांक 8400 घनमीटर था जो उनकी स्वीकृत मात्रा 4500 घनमीटर से 3900 घनमीटर अधिक था।

नियमानुसार 3900 घनमीटर का 2%, 78 घनमीटर को छोड़कर 3822 घनमीटर पर वक्रय मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना था-

(क) रायल्टी

194.50 घनमीटर X3822 घनमीटर

=₹743379.00 का 50% =₹371689.00

(ख) रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15%

=371689 का 15% =₹55753

(ग) विकास शुल्क रायल्टी का 10%

₹371689.00 का 10% =₹37168

कुल=₹464610.00/-

अतः भण्डारणकर्ता पर ₹2.00 लाख अर्धदण्ड तथा रायल्टी ₹464610 का पांच गुना ₹2323050 की वसूली अपेक्षित थी।

स्टोन क्रेशर स्वामी श्री धर्म सिंह भण्डारी पुत्र स्व0 श्री इन्दु सिंह भण्डारी ग्राम-हेलंग, तहसील जोशीमठ जनपद चमोली की ग्राम हेलंग में दिनांक 01 मार्च, 2016 को 200 टन प्रतिदिन क्षमता का स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु 05 वर्ष की अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत स्थल पर पूर्व से जल वद्धुत परियोजना के द्वारा परियोजना निर्माण से निकले मक/पत्थर को भण्डारित किया गया था तथा पत्थर की पैमाद्वारा निम्न प्रकार था-

लम्बाई 70 मीटर X गहराई 5 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर = 5250 घनमीटर

जिस पर निम्नानुसार रायल्टी का गणना किया जाना था-

(क) रायल्टी

194.50 घनमीटर X 5250 घनमीटर

- 1021125 का 50% =510562
 (ख) रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15%
 =510562का 15% =₹76584
 (ग) वकास शुल्क रायल्टी का 10%
 =510562 का 10% =₹51056

कुल=₹638202/-

₹505313 पूर्व में जमा किये जा चुके थे, अतः अवशेष ₹132889 (638202-505313) रायल्टी के रूप में और जमा होना शेष था।

2. स्टोन केशर स्वामी श्री जगदीश सह पवार पुत्र स्व० सुरेन्द्र सिंह पवार ग्राम व पोस्ट पाण्डुकेश्वर तहसी जोशीमठ द्वारा स्टोन केशर संयंत्र की स्थापना हेतु भूमि के समतलीकरण एवं मार्ग से निकले उपखनिज पत्थर के उपयोग हेतु निरीक्षण के समय पत्थर की औसतन पैमाईश 5325 घनमीटर थी तथा वभाग द्वारा समतलीकरण से निकले कुल 5325 घनमीटर उपखनिज पत्थर की रायल्टी पर्वतीय क्षेत्र (क्षेत्र-क) हेतु निर्धारित रायल्टी की (रायल्टी का 50% + 15% रिवर ट्रेनिंग+10% वकास शुल्क) धनराश 96.25 घनमीटर की दर से कुल ₹512531.25 अर्थात् ₹512531. निर्धारित की गयी एवं दिनांक 22 अगस्त, 2016 की चालान संख्या 33 से जमा की गयी।

जब क रायल्टी की गणना नियमानुसार निम्न प्रकार से कया जाना था।

(क) रायल्टी

194.50 घनमीटर X 5325 घनमीटर
 =1035712.50 का 50% =₹517856.25

(ख) रिवर ट्रेनिंग रायल्टी का 15%

517856.25 का 15% =₹77678.43

(ग) वकास शुल्क रायल्टी का 10%

=517856 का 10% =₹51785.62

कुल=₹647320

₹512531/- पूर्व में जमा किये जा चुके थे, अतः अवशेष धनराश ₹134789.00 (₹647320-₹512531) रायल्टी के रूप में जमा होना शेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस इंगत कये जाने पर वभाग ने बिन्दुवार निम्न उत्तर दिये-

- 1- जिला धकारी महोदय चमोली के आदेश सं 5256 तीस-42 उपखनि भण्डारण (2015-16) दिनांक 15 जून 2016 के द्वारा आवेदक को उसके द्वारा उपखनिज के भण्डारण हेतु आवेदति उपलब्ध क्षेत्रफल 0.150 है० पर एक बार में कुल 4500 घनी मी० उपखनिज (बालू, रेत कंकरीट) के भण्डारण की अनुज्ञप्ति स्टोन केशर की अनुज्ञा अवध तक अर्थात् दिनांक 01 मार्च 2021 तक की अवध हेतु स्वीकृत है। स्वामी उपखनिज भण्डारण अनुज्ञप्ति धारक द्वारा क्षेत्रफल के अनुसार तथा भण्डारण नियमावली के अनुसार एक बार में तीन मी० की उचाई तक उपखनिज को एकत्रित कर सकता है। परन्तु वक्रय की गयी मात्रा कम होने या समाप्त होने की अवध के अन्तर्गत क्रय भी कर सकता है।
- 2- त्रुटिवश नदी तल उपलब्ध उपखनिज की रायल्टी निर्धारित कर मात्र आगणन आख्या प्रेषत की गयी थी। इस संबंध में आवेदक से अवशेष रायल्टी की धनराश ₹132890 निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कर दी गई है।
- 3- मूल्यांकन आख्या त्रुटिवश नदी तल पर उपलब्ध उपखनिज (बालू, खजरी, बोल्टर) की निर्धारित आगणत दर के आधार पर लगाये गयी थी। आवेदक द्वारा पूर्व में जमा रायल्टी की अवशेष धनराश का कोषागार चालान द्वारा ₹134789/- निर्धारित लेखाशीर्षक में कया जा चुका है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक बार में तीन मीटर की उँचाई तक उपखनिज को एकत्रित कर सकने तथा भण्डारण नियमावली के अनुसार उक्त क्षेत्रफल 0.150 है० में कतना उपखनिज एकत्रित कया जा सकता है, के आधार पर ही भण्डारणकर्ता को एक बार में 4500 घन मीटर तक ही भण्डारण करने की अनुमति थी। इससे स्पष्ट है क भण्डारणकर्ता द्वारा स्वीकृत उचाई से अधिक उचाई तक उपखनिज का भण्डारण कया गया। अवशेष रायल्टी की धनराश ₹132890 एवं ₹134789 के जमा चालान भी उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः स्वीकृत मात्रा से अधिक भण्डारण पर अर्थदण्ड 2.00 लाख एवं रायल्टी 25.91 लाख के अनारोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 04-मा सक अग्रम कस्त जमा न कये जाने से राजस्व क्षति ₹73.80 लाख

जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के ग्राम अबगांव खसरा सं 127 मु0 क्षेत्र 3.001 हे0 में उपखनिज के खनन हेतु निवदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिला धकारी चमोली द्वारा सर्वाधिक निवदा दाता श्री हरीश सिंह भण्डारी पुत्र श्री मुरली सिंह भण्डारी के पक्ष में मासिक अग्रम कस्त 2000000 तथा प्रतिभूति अग्रम 4000000 जमा करने के उपरान्त दिनांक 11.02.15 को खनन पट्टा आदेश (एम0एम0-10) निम्न शर्तों के साथ दिया गया क-

अग्रम मासिक कस्त जमा करने के उपरान्त ही खनन/खुगान के परिवहन हेतु एम0एम-11 निर्गत किया जायेगा तथा अग्रम जमा न करने की स्थिति में 15% वार्षिक ब्याज के साथ जमा करने का नोटिस जारी करेगा पुनः जमा न करने की स्थिति में 18% की दर से ब्याज सहित कस्त जमा करेगा।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पट्टा धारक द्वारा मात्र एक माह का अग्रम कस्त जमा किया गया था तथा खुगान/खनन तीन माह 02/15, 03/15 एवं 04/15 में किया गया था, इस प्रकार पट्टाधारक (श्री हरीश चन्द्र भण्डारी) द्वारा दो माह का कस्त ₹4000000 सम्प्रेक्षा तिथि तक जमा न करने से राजस्व क्षति हुई थी तथा उक्त पर ब्याज भी देय है।

पुनः उक्त पट्टे को लाटरी सिस्टम के आधार पर मासिक कस्त ₹75250 के आधार पर श्री प्रेम सिंह रावत के पक्ष में दिनांक 12.02.16 का आवंटित कर दिया गया जो कि 30.09.16 तक के लिये वैध था पुनः पट्टा धारक श्री प्रेम सिंह रावत द्वारा माह 06/16 का मासिक कस्त ₹750250/- सम्प्रेक्षा तिथि तक जमा नहीं किया गया था जिस कारण राजस्व क्षति के साथ-साथ ब्याज की हानि भी हुई।

इस प्रकार उक्त लाटरी पर कुल 4750250/- की राजस्व क्षति तथा ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ के ग्राम लाटा खसरा सं 69 मा0 क्षेत्र 04 हे0 में उपखनिज के खनन/खुगान हेतु अल्पकालिक निवदा प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए जिला धकारी चमोली द्वारा सर्वाधिक निवदा दाता श्री धन सिंह राणा पुत्र श्री लाल सिंह राणा के पक्ष में मासिक अग्रम कस्त ₹814815 जमा करने के उपरान्त दिनांक 24.04.15 को खनन पट्टा आदेश पूर्व वर्णित शर्तों के साथ निर्गत कर दिया गया।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा दो माह का (05/16 एवं 06/16) कश्त 1629630/- जमा न करने से राजस्व क्षति हुई तथा उक्त पर ब्याज भी देय है।

उपरोक्त दोनों पट्टा दिनांक 30 सितम्बर 2016 तक ही वैध था, जो कि वर्तमान में समाप्त हो चुका है तथा उक्त धनराशि सम्प्रेक्षा तिथि तक जमा नहीं किया गया था।

उक्त कमियों के संबंध में इंगत किये जाने पर वभाग द्वारा उत्तर में नोटिस भेजे जाने के बात स्वीकार की है तथा प्रतिभूति से समायोजन किया जायेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्प्रेक्षा तिथि तक समायोजन नहीं किया गया था तथा लाट/पट्टा की अवधि समाप्त हो गयी है। अतः मासिक कस्त ₹ 63.80 लाख जमा न किये जाने से राजस्व क्षति तथा ब्याज के हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'ब'

प्रस्तर 5: शासनादेश में दिये गये नियमों की अनदेखी से राजस्व क्षति ₹0.50 लाख

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, अधिसूचना संख्या-96/VII-1/2016/158-ख/2004 देहरादून, 22 जनवरी, 2016 के नियम-8(2) के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र खनिज भण्डारण हेतु 1000 धनमीटर तक के लये आवेदन शुल्क 0.25 लाख (पच्चीस हजार) तथा इसमें अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 धनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त ₹0.25 लाख आवेदन शुल्क देय होगा।

पुनः नियम 10 खनिज भण्डारण के लये अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व नियम 8(2) में निर्धारित आवेदन शुल्क एवं पूर्व अनुज्ञप्ति के ववरण सहित जिला अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

कार्यालय जिला खनिज अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) की लेखा परीक्षा में भण्डारण पत्रावलयों की जांच में पाया गया कि मैणकुंवर स्टोन क्रेशर द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह कुंवर, ग्राम क्षेत्रफल तहसील व जिला चमोली की दिनांक 24 जून, 2016 तक खनिजों के भण्डारण की अनुमति थी। शासनादेश की अनुसार आवेदक की कम से कम दो माह पूर्व अर्थात् दिनांक 24 अप्रैल, 2016 तक निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना था एवं 5970 घनमीटर उपखनिज के भण्डारण हेतु 1.50 लाख आवेदन शुल्क देय था। जबकि आवेदनकर्ता द्वारा नियम विरुद्ध दिनांक 04.04.16 को आवेदन शुल्क के रूप में 1.00 लाख जमा किये गये। इस प्रकार ₹0.50 लाख के राजस्व की क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इस इंगत किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि आवेदक द्वारा दिनांक 06.06.16 की उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था तत्समय शासनादेश सं० 851/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनांक 19.05.16 प्रस्तावित था। उक्त नियमावली के बिन्दु सं 8(2) में स्टोन क्रेशर की खनिज भण्डारण हेतु ₹100000/- आवेदन शुल्क निर्धारित है। उक्तानुसार कसी प्रकार की राजस्व क्षति नहीं हुई।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि शासनादेश का पालन किया गया होता तो आवेदनकर्ता द्वारा नियमानुसार 1.50 लाख जमा किया जाता, शासनादेश आवेदनकर्ता द्वारा कम से कम दो माह पूर्व आवेदन करने में चूक का परिणाम हुआ कि वभाग 0.50 लाख के राजस्व से वंचित हो गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण : प्रथम
लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
लागू नहीं		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला खनन अधिकारी गोपेश्वर (चमोली)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: 1. अवैध घनन एवं परिवहन से संबंधित पत्रावल्यां
2. **सतत् अनियमितताएं:**
टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	खान अ धकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खनन अधिकारी गोपेश्वर (चमोली)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी राजस्व क्षेत्र